ए-45011/4/2023- समन्वय.II

भारत सरकार

वित्त मंत्री

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को फरवरी, 2023 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सार के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश दिया जाता है।

अरूप श्याम

(अरूप श्याम चौधरी)
उप सचिव, भारत सरकार
फोन नं. 2309- 5054

सेवा में,

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्यमंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी.अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सीएंडसी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (जी-20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-॥)/ओएमआई/क्रिप्टो आस्तियां और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग में सभी प्रभागों के प्रमुख।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी) /संयुक्त सचिव (आईएनवी)/ संयुक्त सचिव (बजट) संयुक्त सचिव (वित्त मंत्री)/सभी सलाहकार/सीएएए
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल - 2023

ए-45011/4/2023- समन्वय.II

भारत सरकार
वित्त मंत्री
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

विषय: फरवरी, 2023 के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश

1. फरवरी माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

वृह्त आर्थिक सिंहावलोकन:

फरवरी, 23 की तीसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि, फरवरी, 22 की तीसरी तिमाही के आधार पर अनुमानित, 4.4 प्रतिशत पर आ गई है। दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि मुख्य रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों, खनन और उत्खनन, निर्माण और आपूर्ति पक्ष से संपर्क-गहन सेवा क्षेत्रों और मांग पक्ष से निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) से बनी हुई है।

तीसरी तिमाही में लचीले आर्थिक विकास की समावेशिता भी रोजगार संकेतकों में सुधार में दिखाई देती है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए समग्र शहरी बेरोजगारी दर 2021 की दिसंबर तिमाही में 8.7 प्रतिशत से घटकर एक साल बाद 2022 के दिसंबर में 7.2 प्रतिशत हो गई। ईपीएफओ के तहत नेट पेरोल में दिसंबर 2022 में 41.4 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि देखी गई, जो दर्शाता है कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार ने रिकवरी के चरण को पार कर लिया है और विकास में वृद्धि दर्ज कर रहा है। फरवरी 2023 में 9 प्रतिशत की क्रमिक मासिक वृद्धि को देखते हुए, नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स समग्र भर्ती गतिविधि में वृद्धि को दर्शाता है।

गिरती अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों और सरकारी उपायों ने फरवरी 2023 में मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने में मदद की है। सीपीआई मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में 6.5 प्रतिशत की तुलना में फरवरी 2023 में 6.44 प्रतिशत पर आ गई। फरवरी 2023 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति के 25 महीने के निचले स्तर 3.85 प्रतिशत पर आने के साथ, जल्द ही इसका सीपीआई मुद्रास्फीति में संचरण होने की उम्मीद है।

विश्लेषण से पता चलता है कि भारत उन कुछ देशों में से एक है, जिनके पास 2008 की इसी तिमाही की तुलना में 2022 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कम कॉर्पोरेट ऋण है। कर्ज में कमी के साथ-साथ क्रेडिट चक्र में डेलेवरेजिंग चरण के परिणामस्वरूप 2021 के मध्य से गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है, जो भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षाकृत कम ऋण-वित्तपोषित मजबूत वसूली का प्रतिबिंब है। भारत का

कॉर्पोरेट क्षेत्र क्रेडिट-जीडीपी अनुपात भी अपने ऐतिहासिक रुझान से नीचे है, जो कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए अपने कर्ज के बोझ को बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह का संकेत देता है। कॉर्पोरेट क्षेत्र की मजबूत ऋण प्रोफ़ाइल अर्थव्यवस्था की व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हुई है।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) माननीय वित्त मंत्री ने **1 फरवरी, 2023 को 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट** पेश किया।

(ii) इस महीने के दौरान जी-20 **इंडिया प्रेसीडेंसी के तहत निम्नलिखित वित्त ट्रैक बैठकें** आयोजित की गईं:

क) भारत के माननीय वित्त मंत्री और भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर की संयुक्त अध्यक्षता में पहली जी-20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (एफएमसीबीजी) की बैठक 24-25 फरवरी, 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। बैठक का मुख्य प्रदेय जी-20 अध्यक्ष का सारांश और परिणाम दस्तावेज़ था जिस पर 22-23 फरवरी, 2023 के दौरान जी20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा बातचीत की गई थी।

ख) पहली जी-20 एफएमसीबीजी बैठक के दौरान निम्नलिखित साइड इवेंट/संबंधित बैठकें आयोजित की गईं:

- माननीय वित्त मंत्री ने जी-**20** में आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इटली, अमेरिका, जापान, कनाडा, अर्जेंटीना, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प, स्पेन, इंडोनेशिया, बीआईएस, यूरोपीय आयोग, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

- माननीय वित्त मंत्री ने आईएमएफ से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, एमडी, आईएमएफ और सुश्री गीता गोपीनाथ, एफडीएमडी आईएमएफ के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

- माननीय वित्त मंत्री ने सुश्री नादिया कैल्विनो, स्पेन की प्रथम उप प्रधान मंत्री और आईएमएफसी अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक की।

- मंत्रिस्तरीय और वित्त प्रतिनिधियों के स्तर पर भागीदारी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए, जैसे,

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) पर उच्च स्तरीय संगोष्ठी;

- 'नीतिगत परिप्रेक्ष्य: क्रिप्टो आस्तियों पर नीतिगत सहमति के मार्ग पर चर्चा' और 'सीमा पार भुगतान व्यवस्था को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली का लाभ उठाना' पर सेमिनार;

- वित्त मंत्रियों, केन्द्रीय बैंक के गवर्नरों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और उनके प्रतिनिधियों के लिए 'वॉक द टॉक: पॉलिसी इन एक्शन' कार्यक्रम, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु का विशेष दौरा शामिल है।

ग) आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेशन और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के जी-20 कार्यदल की पहली बैठक आभासी रूप से श्री अमिताभ कांत (भारत के जी-20 शेरपा) और श्री नंदन नीलेकणि की अध्यक्षता में हुई थी।

(घ) 2-3 फरवरी, 2023 के दौरान गुवाहाटी में जी-20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप (एसएफडब्ल्यूजी) की पहली बैठक हुई। इस बैठक के साथ-साथ, 'सतत वित्त को बढ़ाने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का क्षमता-निर्माण' पर एक जी-20 कार्यशाला और 'एसडीजी के लिए वित्तपोषण: सतत भविष्य प्राप्त करने के लिए ब्लूप्रिंट'' पर जी-20 पैनल चर्चा और 'एसडीजी के वित्तपोषण में वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों की भूमिका' और जनभागीदारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

(iii) माननीय वित्त मंत्री ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकों में भाग लिया:

(क) आईएमएफ से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, एमडी, आईएमएफ के साथ आभासी रूप से बैठक।

(ख) विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डॉ डेविड आर मेलपास के साथ बैठक।

(iv) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित ऋण/अनुदान करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

(क) निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए जापान सरकार के साथ नोटों के आदान-प्रदान पर हस्ताक्षर किए गए और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए:

- मिजोरम राज्य सुपर-स्पेशियलिटी कैंसर और अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 9.918 बिलियन जापानी येन (लगभग 560 करोड़ रुपये) का ऋण।

- मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक परियोजना (III) के लिए 30.755 बिलियन जापानी येन (लगभग रु. 1,728 करोड़) का ऋण

(ख) "हरित और सतत विकास साझेदारी" के तहत विभिन्न विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वर्ष 2022 के लिए वित्तीय सहयोग (एफसी) अंब्रेला करार पर जर्मनी के साथ 899.50 मिलियन यूरो (880 मिलियन यूरो का ऋण और 19.50 मिलियन यूरो का अनुदान) के लिए हस्ताक्षर किए गए थे।

(v) इस माह के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) आईआईबीएफ, मुंबई में आयोजित परियोजना वित्त पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) आईआईएम, कोझीकोड में आयोजित परियोजना प्रबंधन और पीपीपी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ग) एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद में आयोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एक बुनियादी परिप्रेक्ष्य।

(vi) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें/कार्यशालाएं आयोजित/में भाग लिया गया:

(क) सचिव (आर्थिक कार्य) ने आभासी रूप से दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की पहली बैठक में भाग लिया।

(ख) लंदन में भारत-यूके बीआईटी वार्ता का 7वां दौर।

(ग) डीवीसे के माध्यम से आयोजित भारत-कंबोडिया बीआईटी चर्चा का चौथा दौर।

(घ) डीवीसी के माध्यम से आयोजित भारत-सऊदी अरब बीआईटी चर्चा का पांचवां दौर।

(ङ) बेंगलुरु में आयोजित जी20 वित्त प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक।

(च) वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने 2023 में क्रिप्टो-आस्तियों और डीईएफआई पर एफएसबी के काम और जी-20 के प्रदेय (डिलिवरेबल्स) सहित एफएसबी कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए संचालन समिति की बैठक आयोजित की।

(छ) एफएसबी ने प्रतिपूर्ति ढांचे में जलवायु जोखिम कारकों, सुधार प्रभावशीलता विश्लेषण नेटवर्क कार्य योजना, मुद्रा बाजार कोष (एमएमएफ) सुधारों पर विषयगत समीक्षा पर चर्चा करने के लिए एससीएसआई बैठक आयोजित की।

(ज) एआईआईबी निदेशक मंडल ने निवेश परियोजनाओं पर विचार करने और कोविड-19 संकट रिकवरी सुविधा (सीआरएफ) की दूसरी अंतरिम समीक्षा के लिए वर्चुअल बैठक की।

(झ) आईएफएडी की 46वीं शासी परिषद की बैठक रोम में आयोजित की गई।

(ञ) वित्त वर्ष 23 में एसएआरटीटीएसी के संचालन और कार्यकलापों, द्वितीय चरण के लिए एसएआरटीटीएसी बजट और वित्त वर्ष 24 के लिए एसएआरटीटीएसी की कार्ययोजना और प्रशिक्षण कैलेंडर पर चर्चा करने के लिए अपर सचिव (एमबीसी) ने एसएआरटीटीएसी की अंतरिम संचालन समिति की बैठक में भाग लिया।

(ट) बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय संस्थाओं से वित्तपोषण प्राप्त करने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग जांच समिति की 137वीं बैठक आयोजित की।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी के निदेशों/आदेशों का अनुपालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन के लिए प्रतीक्षारत एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	:	शून्य
विभाग में स्वीकृति का इंतजार	:	07